मुरैना में जन आभार यात्रा में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का जगह-जगह स्वागत, कांग्रेस ने रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा का

न्यौता ठुकराकर हिंदुओं का किया अपमान : डॉ. यादव

भोपाल (काप्र)।

भाजपा मध्यप्रदेश को विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर मुरैना में आयोजित जन आभार यात्रा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर का जगह-जगह ऐतिहासिक स्वागत किया गया।

राधिका पैलेस होटल के पास से कृषि उपज मंडी प्रांगण तक निकाली गई जन आभार यात्रा में स्थानीय लोगों ने मंच बनाकर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का पुष्पवर्षा और बड़ी मालाओं से भव्य स्वागत किया। जन आभार यात्रा के बाद डॉ. यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुरैना में बंद पड़ी शक्कर फैक्ट्री पर किसानों के बकाया 56 करोड़ रूपए देने के साथ प्रदेश भर में बंद पड़ी मिलों, फैक्ट्रियों पर किसानों और मजदूरों के बकाया को प्रदेश सरकार वापस करेगी। चंबल क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सके। कांग्रेस सरकार ने 20 साल तक पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना को रोके रखा। विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में चंबल क्षेत्र का द्रुतगति से विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने साढ़े तीन हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कर चुके हैं। आगरा से ग्वालियर के मध्य नए एक्सप्रेस वे से साढ़े तीन घंटे में मुरैना से नई दिल्ली पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने मुरैना कृषि उपज मंत्री प्रांगण में राय स्तरीय रोजगार दिवस पर आयोजित समारोह में एक साथ 7 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए 5151 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया। मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार के लिए ऋण प्राप्त करने वाली चार महिलाओं से चर्चा भी की। प्रदेश के सभी जिले समारोह से वर्चुअली जुड़े। सभा को संबोधित करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति की अच्छाई आक्रांओं को खटकती थी। आजादी से पहले और बाद देश की सीमाओं पर जितने भी आक्रमण हुए हैं, सभी में भिंड और मुरैना जिले के वीर सपूतों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। चंबल के रणबांकुरे हजारों साल से हिंदू संस्कृति का मान-सम्मान बढ़ा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भिंड और मुरैना में जो मिल व फैक्ट्रियां बंद पड़ी होंगी, उन्हें चालू कराया जाएगा। 2003 में मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद पार्वती-कालीसिंध-चंबललिंक परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया गया। डॉ. यादव ने कहा कि 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई और परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस परियोजना को मूर्त रूप देने के प्रयास हुए तो कुछ महीनों बाद ही राजस्थान में कांग्रेस सरकार बन गई। अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्यप्रदेश, राजस्थान में भाजपा सरकारें बनीं तो परियोजना का मूर्त रूप दिया गया। 75 हजार करोड़ की लागत वाली इस परियोजना में 7 बड़े बांध बनाए जाएंगे। इस परियोजना से चंबल क्षेत्र के बीहड़ों तक पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे खेती के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में चंबल क्षेत्र का द्रुत गति वे विकास होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने चंबल क्षेत्र में तीन हजार करोड़ की सड़क परियोजनाओं को गत दिनों शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में उद्योग लगाने को भी कहा है। शनिचरा मंदिर के विकास और मुरैना में एलिवेटेड रोड, बायपास बनाने पर भी सहमति दी है। पहले इस क्षेत्र में छोटी लाइन पर रेल चलती थी, अब बड़ी लाइन का कार्य चल रहा है। रेल सबलगढ़, शिवपुरी होते हुए राजस्थान के कोटा पहुंचेगी। अब आगरा यमुना एक्सप्रेस वे से सीधा ग्वालियर बायपास पर एक्सप्रेस वे उतरेगा। चार हजार करोड़ इसकी लागत आएगी और 3:30 घंटे में मुरैना से व्यक्ति दिल्ली में पहुंच जाएंगे।

इस अवसर पर प्रदेश शासन के मंत्री एंदलसिंह कंसाना, राकेश शुक्ला, जिलाध्यक्ष डॉ. योगेशपाल गुप्ता, विधायक सबलगढ़ श्रीमती सरला रावत, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती आरती गुर्जर, पूर्व विधायक गिर्राज दंडोतिया, पूर्व मंत्री मुंशीलाल जाटव, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, जिला संगठन प्रभारी जयसिंह कुशवाहा, पूर्व सांसद अशोक अर्गल, पूर्व विधायक रघुनाथ कंसाना, सूबेदार सिंह राजौधा, परशुराम मुदगल, राकेश मवई, सत्यप्रकाश सखवार, कमलेश जाटव, बारेलाल जाटव, नागेंद्र तिवारी, केदार सिंह यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष अनूप सिंह भदोरिया सहित जिला पदाधिकारी उपस्थित थे।

चम्बल क्षेत्र में पर्यटन, कृषि, उद्योगों के माध्यम से रोजगार देना प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जरूरतमंदों को रोजगार देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने पर्यटन, वन, खनिज, उद्योग व सेवा क्षेत्र सहित सभी सेक्टर में रोजगार देने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। चम्बल संभाग असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। यहां रोजगार और विकास के लिये कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जायेगा। कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता और सूक्ष्म, लघु उद्योग विभाग कार्ययोजना प्रस्तुत करें। कार्ययोजना में हर सेक्टर से जरूरतमंदों को रोजगार मिले, इसकी जिलेवार तैयारी करें। डॉ. यादव मुरैना कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई संभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्बल-मुरैना क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ ऐतिहासिक इमारतें, जलाशय व अकूत वन संपदा उपलब्ध है। इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये रोजगारपरक योजना तैयार करें। जिले से लेकर संभाग तक ऐसी बैठकें निरंतर की जायेगी। डॉ. यादव ने कहा कि हर जिले में ऐसे सक्षम लोग मौजूद हैं, जो थोड़े से प्रोत्साहन और सरकारी मदद से उद्यम स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सक्षम लोगों से संवाद कर उन्हें रोजगार के अवसर पैदा करने व उद्यम खड़ा करने के लिये प्रेरित करें।

डॉ. यादव ने बैठक में निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्गों के नजदीक बसे गाँवों को नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी अनिवार्यत: मिले। साथ ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माणाधीन हैं, वहाँ विशेष ध्यान देकर संबंधित ग्रामों को मुख्य सड़कमार्ग से जुड़वाएँ। राजधानी दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहरों से निकट होने के कारण क्षेत्र में उद्योगों की असीम संभावना है, इसके लिये बड़े उद्योग, कपड़ा क्लस्टर, फर्नीचर, ग्रामोद्योग और खाद्य प्रंसस्करण उद्योगों को बढ़ावा देंगे। बड़े उद्योग समूह को बुलाकर औद्यौगिकीकरण के लिये काम हों। मुरैना चंबल संभाग में पर्यटन की असीम संभावना है। यहां पर चंबल में डॉल्फिन, घड़ियाल, पढावली, मितावली, बटेश्वर, शनिमंदिर और ऐसे ही अनेक पर्यटन स्थल हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरने के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलारस शक्कर करखाने पर किसानों की बकाया राशि का भुगतान कराया जाएगा। लगभग 54 करोड़ की शेष राशि का भुगतान कार्ययोजना बनाकर किया जायेगा। इसके साथ ही लघु और सूक्ष्म उद्योग विभाग, सहकारिता विभाग के साथ रोजगारोन्मुख उद्योग लगाने के लिए कार्य योजना बनाई जायेगी। चंबल नदी के इको सिस्टम के अनुसार क्षेत्र का विकास किया जाएगा। चंबल असीम संभावनाओं का क्षेत्र है, यहाँ का युवा मेहनत कश है। यहां से हजारों युवा हर साल सेना की भर्ती में जाते है। वीरों की भूमि पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने आयुक्त ग्वालियर-चंबल संभाग श्री दीपक सिंह को निर्देश दिए कि श्योपुर जिले में सहरिया जनजाति के लोगों के जाति प्रमाण-पत्र बनाकर उनके घर पहुँचाने की व्यवस्था की जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल जीवन मिशन से संबद्ध विभाग समन्वयपूर्वक बैठक आयोजित करें और जल स्त्रोतों के अनुरूप पेयजल समस्याओं को दूर करें। डॉ. यादव ने बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों से कहा कि हम सभी को मिलजुलकर प्रदेश को ऊँचाईयों पर ले जाने के लिये कार्य करना है। इसमें किसी भी प्रकार की मत भिन्नता आड़े नहीं आयेगी। सरकार दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी के सुझावों को सम्मान देगी और अच्छे सुझावों पर अमल करेगी।

सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी कप में शामिल हुए मंत्री पटेल

भोपाल (काप्र)।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल गुरुवार को नरसिंहपुर जिले की ग्राम पंचायत बगासपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी कप के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टेनिस टूर्नामेंट के समापन में शामिल हुए।

इस अवसर पर उन्होंने कुल 55 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम में विधायक महेंद्र नागेश, पूर्व विधायक जालम सिंह पटेल, श्री हाकम सिंह सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य हर पात्र जरूरतमंद व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजना का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि गांव में गौशाला का निर्माण कर नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए गायों को गौशालाओं में रखा जाये, इसके लिए हम सबको आगे आना होगा। हमें आज लोगों को समझाना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों को नई ऊंचाइयों पर लाने के लिए सभी का सहयोग महत्वपूर्ण है। ग्रामों में पेयजल एवं

स्वच्छता की अलख जगानी होगी। गंदे पानी को स्वच्छ जल स्त्रोतों में मिलने से रोकना होगा। इसके लिए जल प्रबंधन की महती आवश्यकता है। इस पानी का हम पुन: उपयोग कर सकते हैं। हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करना होगा। श्री पटेल ने कहा कि बच्चों की मोबाइल की आदत को छुड़ाकर उन्हें खेल के मैदान में पहुंचाना होगा जिससे उनका विकास हो सके। युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए खेल के मैदान मददगार साबित होंगे। खेल हमारे जीवन में अद्वितीय महत्व रखता है।

डॉ. यादव के मुख्य आतिथ्य में विश्व वेटलैंड्स दिवस आज इंदौर में

भोपाल (काप्र)।

विश्व वेटलैंड्स दिवस-2024 का मुख्य कार्यक्रम शुक्रवार को इंदौर शहर के सिरपुर तालाब में होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि और केन्दीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

विश्व वेटलैंड्स दिवस कार्यक्रम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सह आयोजक, म. प्र. राज्य वेटलैंडप्राधिकरण, पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन तथा नगर पालिक निगम, इन्दौर के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। विश्व वेटलैंड्स दिवस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों वेटलैंडर प्राधिकरण के अधिकारी, वैज्ञानिक तथा देश की 80 रामसर साइट्स के प्रबंधक सहित 200 से अधिक विशेषज्ञ सम्मिलित हो रहे हैं। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, पर्यावरण एवं वन मंत्री नागर सिंह चौहान, पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार, सांसद श्री शंकर लालवानी, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, स्थानीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ एवं रामसर सचिवालय की महासचिव डॉ. मुसोन्दामुम्बाश भी उपस्थित रहेंगी।

प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा : सारंग

भोपाल (काप्र)।

सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सहकारिता आंदोलन समाज के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। समाज, परिवार, प्रदेश और देश समन्वय और परस्पर सहयोग के बगैर नहीं चल सकते हैं। सहकारिता की समाज में अहम भूमिका है।

प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाया जायेगा। सहकारिता के माध्यम से समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। रोजगार के नए अवसर सृजित किये जायेंगे। यह बात मंत्री श्री सारंग ने आज इंदौर में सहकारिता और इससे जुड़े विभागों के अधिकारियों की संभागीय समीक्षा बैठक में कही। श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने तथा उसको विस्तारित करने के लिये सहकारिता विभाग अब नए कलेवर और नयी सोच के साथ कार्य करेगा। इसके लिये बहुवर्षीय रोडमैप बनाकर सहकारिता आंदोलन में नयी तकनीक को शामिल करते हुए प्रक्रिया सुधार के कार्य किये जायेंगे। सहकारिता आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों को साकार किया जायेगा।

श्री सारंग ने कहा कि अधिकारी विभाग में नवाचार करते हुए नयी सोच, पारदर्शिता एवं पूर्ण ईमानदारी से निष्ठावान होकर कार्य करें। भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करें। को-ऑपरेटिव बैंकों को प्रायवेट बैंकों के अनुरूप बनायें। इसे नए कलेवर में कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह प्रस्तुत करें। समय की आवश्यकता के अनुसार कार्य एवं व्यवहार में बदलाव लाये। जन-कल्याण के अधिक से अधिक कार्य करें। सहकार से समृद्धि की ओर प्रदेश को आगे बढ़ाये।

श्री सारंग ने कहा कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के रिक्त सभी पदों की पूर्ति सुनिश्चित करें। सहकारी समितियों में अधिक से अधिक महिला सदस्यों को जोड़ें। एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत सहकारी सोसायटियों का गठन करें। इन्हें आर्थिक मदद देकर आगे बढ़ायें। को-ऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से मोबाइल साँची पार्लर की स्थापना कराई जाये।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का किया निरीक्षण

भोपाल (काप्र)। उप मुख्यमंत्री ने राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज जबलपुर एवं अस्पताल में पद पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएं। उच्च पद का प्रभार देने की कार्यवाही प्राथमिकता से करें। नगर निगम के शेष रह गए वार्ड में संजीवनी क्लीनिक बनाएं और मैन पावर उपलब्ध कराया जाएं। उप मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड धारियों को सहज उपचार मुहैया कराने के निर्देश दिये। उन्होंने अधोसंरचनात्मक विकास के विषयों पर विस्तार से चर्चा कर नर्सिंग कॉलेज के कार्यों को डीपीआर में शामिल करने के निर्देश भी दिये। श्री शुक्ल ने गुरुवार को मेडिकल कॉलेज जबलपुर एवं चिकित्सालय की सामान्य परिषद की बैठक में चिकित्सा व्यवस्था सुविधाओं, बजट, सभी श्रेणी के पदों की स्थिति, रिक्तियां, उपकरणों के रखरखाव, सफाई और सुरक्षा और भविष्य की कार्ययोजना की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये। उपमुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

स्पेशल खबर व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के परिप्रेक्ष्य और प्रथाएं विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रारंभ...

पारंपरिक कारीगरों तक पहुंचे आधुनिक तकनीकयुक्त व्यावसायिक शिक्षा: परमार

भोपाल (काप्र)।

भारतीय पारंपरिक कौशल को आधुनिक तकनीक के अनुप्रयोग एवं व्यावसायिक पद्धति के साथ नवीन आयाम देने की आवश्यकता है। गांव के कारीगरों के पास परंपरागत प्रतिभा है, लेकिन तकनीक तथा व्यावसायिक कौशल के अभाव में काम की तुलना में उनकी आमदनी कम होती है।

उन कारीगरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उनके कार्य में तकनीक को शामिल करें, जिससे वे अपनी पारंपरिक प्रतिभा के अनुरूप लाभ प्राप्त कर सकें। यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने गुरुवार को पं. सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीआईवीई) भोपाल के निनाद सभागार में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के परिप्रेक्ष्य एवं प्रथाएं विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर कही।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने कहा कि व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम, केवल अध्यापन तक सीमित न होकर मानव जीवन को बेहतर बनाने की दिशामूलक हो जिससे लोगों की प्रगति और जीविकोपार्जन के लिए बेहतर स्त्रोत उपलब्ध हो सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परम्परा के सामंजस्य और तालमेल के लिए अपने कला, पारंपरिक कौशल और प्रतिभा को गर्व के भाव के साथ प्रसारित करने की आवश्यकता है। श्री परमार ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की विकसित भारत की संकल्पना अनुरूप युवा पीढ़ी को विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति और सफलता की दिशा में व्यावसायिक शिक्षा के महत्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता की बात कही। श्री परमार ने शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर संकलित पुस्तिका का विमोचन किया।

संस्थान परिसर में आयोजित कौशल आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान श्री परमार ने परंपरागत कौशल माटीकला के संवर्धन के लिए स्वयं मिट्टी के दीपक बनाने का प्रत्यक्ष प्रायोगिक प्रयास कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने का संदेश दिया।

प्रो. विनय स्वरूप मेहरोत्रा ने बताया कि इस संगोष्ठी के दौरान शोधार्थियों द्वारा विभिन्न थीम पर लगभग 80 शोधपत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें पाठ्यचर्या में उभरती प्रौद्योगिकियों का एकीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में उभरते रुझान, उद्यमिता विकास और लघु व्यवसाय प्रबंधन, समावेशी शिक्षा और विविध कार्यबल, योग्यता-आधारित मूल्यांकन और व्यावसायिक शिक्षा में तकनीकी प्रगति, एनसीएफ-2023 के अनुसार स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में सर्वोत्तम अभ्यास, हरित कौशल और सतत अभ्यास, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में डिजिटल कौशल थीम शामिल हैं। प्रो. मेहरोत्रा बताया कि राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ संस्थान में चार दिवसीय ड्रोन प्रौद्योगिकी में नवाचार, इनक्यूबेशन और उद्यमिता जागरुकता निर्माण को लेकर स्कूली छात्रों के लिए एक बूटकैंप का शुभारंभ किया गया, जिमसें ड्रोन का परिचय, हैंड्स-ऑन ड्रोन पायलटिंग, ड्रोन रखरखाव, ड्रोन बिल्डिंग चैलेंज, ड्रोन रेसिंग प्रतियोगिता जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है।